Zoning Atlas
जोनिंग एटलस

बढ़ती हुई जनसंख्या एवं औद्योगीकरण के साथ–साथ शहरों का विस्तार तीव्र गति से हुआ है, परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अनियमित रूप से बढ़ रहा है। प्रायः यह देखा गया है कि किसी भी स्थान पर संचालित की जाने वाली किसी गतिविधि का उस स्थान पर एवं उसके आस–पास के पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो कि नकारात्मक अथवा सकारात्मक हो सकता है। इन प्रभावों का मूल्यांकन तत्काल संभव न होकर दूरगामी होता है, उदाहरण के लिए – किसी नगर के विस्तार करने के लिए उसके आस–पास के भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। यदि अधिग्रहित भूमि का उपयोग अनियोजित विधि से किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक भू–संरचना (छोटी–बड़ी घाटियों) का समतलीकरण, वनों की कटाई, खुले क्षेत्रों का ढाकना, उपजाऊ भूमि को अन्य उपयोग में लाना आदि गतिविधियॉ सम्मिलित है, तो उसके दुष्परिणाम निम्नानुसार हो सकते हैः–

1. क्षेत्र विशेष में वायु के पथ, दिशा एवं गति में परिवर्तन जिससे क्षेत्र के तापमान में वृद्धि अनिश्चित वर्षा ।
2. जल ग्रहण क्षेत्र में कमी के कारण भू–जल एवं सतही जल के स्तर में गिरावट ।
3. भू–जल संवर्धन में सहायक भू–संरचनाओं के ऊपर एवं खुले क्षेत्रों (जैसे वन, कृषि भूमि आदि) में लगातार निर्माण एवं विकास कार्य के कारण रिचार्जिग में निरंतर कमी व शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति निर्मित होना।
4. वनीकरण एवं उपजाऊ भूमि में लगातार हो रही कमी।
5. उपजाऊ मृदा क्षरण के कारण क्षेत्र में फसल उत्पादन में कमी।
6. ठोस अपशिष्टों का नदी/तालाब में बहाव के कारण जल प्रदूषण तथा जल ग्रहण क्षमता में कमी व बाढ़ की स्थिति निर्मित होना।

उपरोक्त गतिविधियों से जल/वायु प्रदूषण तो होता ही है साथ ही क्षेत्र का सम्पूर्ण पर्यावरण एवं जैव विविधता (पक्षियों का पलायन, जलीय जीवों का मरना, वनस्पतियों का समाप्त होना) आदि भी प्रभावित होती है।

अतः आज की यह आवश्यकता है कि स्थल प्रबंधन अत्यन्त ही वैज्ञानिक, दूरदर्शी एवं नियोजित विधि से किया जावे, जिसमें प्रकृति एवं पर्यावरण के विभिन्न घटकों की न्यूनतम क्षति को दृष्टिगत रखते हुए विकास कार्य किया जा सके।

नियोजित स्थल प्रबंधन

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली) की तकनीकी एवं वित्तीय सहायता से जोनिंग एटलस परियोजना को 1999 से संचालित कर रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों तथा विशेष क्षेत्रों हेतु पर्यावरण पर आधारित एटलस तैयार किये जा रहे है। इसके अन्तर्गत मुख्यतः दो प्रकार के अध्ययन एवं प्रबंधन योजना शामिल हैः–

1. जिलेवार पर्यावरणीय अध्ययन :–

इसके अन्तर्गत बनाए गये पर्यावरण आधारित एटलसों में जिले – विशेष की भौगोलिक स्थिति, भू–जल तथा सतही जल (गुणवत्ता, उपयोग, उपलब्धता,) वायु गुणवत्ता, वर्तमान भूमि उपयोग, ड्रेनेज, टोपोग्राफी, जिले के संवेदनशील स्थल आदि के संबंध में मानचित्र तथा इनका पूर्ण विश्लेषण एवं भूमि–उपयोग संबंधित अनुशंसाओं का उल्लेख किया गया है। इस एटलस में उपरोक्त विषयों पर आधारित लगभग 30 मानचित्रों को संकलित किया गया है। समस्त मानचित्र रिमोट सेंस डाटा, फील्ड डाटा एवं विभिन्न

विभागों से प्राप्त डाटा के आधार पर तैयार किये गये है तथा इनको 1:2,50,000 के स्केल पर जी.आई.एस. तकनीक से विश्लेषित कर प्रस्तुत किया गया है।

संक्षिप्त में कहा जा सकता है, कि यह एक मार्गदर्शिका है जिसके माध्यम से किसी भी विकास गतिविधि को प्रारंभ करने हेतु ऐसा स्थल चयन किया जा सकता है जहॉ गतिविधी विशेष के संचालन के कारण पर्यावरण को असाध्य क्षति न पहुँचे और जो भी विकास हो वह पर्यावरण क्षति के मूल्य पर न हो। इससे निश्चित रूप से विकास अधिक प्रभावी एवं स्थायी होगा।

2. क्षेत्र विशेष पर पर्यावरण आधारित अध्ययन :–

इस अध्ययन के अन्तर्गत मानचित्रों को रिमोट सेंस डाटा, फील्ड डाटा एवं विभिन्न विभागों से प्राप्त डाटा के आधार पर तैयार किये जाते है, तथा इनको 1:50,000 के स्केल पर जी.आई.एस. तकनीक से विश्लेषित कर प्रस्तुत किया गया है, उदाहरण के लिए सतना जिले में स्थित चूना–पत्थर खदानों से आसपास के क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का आंकलन, तदानुसार भविष्य में इससे होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने संबंधित अनुशंसाएँ।

किये गये अध्ययन :–

- आगासौद बीना औद्योगिक क्षेत्र की योजना।
- पर्यावरण प्रबधंन योजनाः–
  - इंदौर – शहर *
  - सतना– चूना की खदानें *
  - पंचमढ़ी–जैव विविधता *
  - पर्यावरण सूचना तंत्र – अमरकंटक–जैव विविधता *

- जिलेवार पर्यावरणीय एटलस एवं जोनिंग एटलस–छिंदवाड़ा, सागर, रायसेन, धार एवं इंदौर। *
- मध्यप्रदेश राज्य का पर्यावरण एटलस **(State Environment Atlas).** *

*सभी रिपोर्टस् केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी है।

वर्ष 2007–08 में किये जा रहे कार्य :–

- उज्जैन एवं देवास जिलों के लिए जोनिंग एटलस।
- मध्यप्रदेश राज्य का पर्यावरण एटलस तथा जिलेवार पर्यावरणीय एटलसों के प्रकाशन का कार्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से किया जाना है।